समक्ष *राजीव भल्ला,* माननीय न्यायमूर्ति।

राजबीर *सिंह,* – याचिकाकर्ताओं

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य , – प्रतिवादियों

सी आर ऐल . *आर. 2005 की संख्या 1297*

29 मार्च, 2006

***दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-* धारा *310*-दहेज की मांग पूरी न करने पर बेटी की मौत पर पिता का दामाद और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस के समक्ष बयान– एक पूरक बयान पर, जिसमें कथित तौर पर पिता द्वारा ससुराल वालों को दोषमुक्त करने और अपनी बेटी के पति और दो दोस्तों को फंसाने का आरोप लगाया गया था।-पुलिस पति और उसके दोस्तों के खिलाफ चालान पेश कर रही है और पति के परिवार के सदस्यों को कॉलम नंबर *2* में डाल रही है – याचिकाकर्ता ने अपने पूरक बयान से स्पष्ट रूप से इनकार किया और आरोपी को तलब करने के लिए धारा *319* के तहत आवेदन दायर किया- धारा *319* ट्रायल कोर्ट को आरोपी को पहले से ही दोषी ठहराए गए आरोपी के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाने की शक्ति प्रदान करता है – ऐसी शक्तियों का प्रयोग कुछ हद तक सावधानी के साथ, असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, न्यायालय संतुष्ट हो कि जिन व्यक्तियों को समन करने की मांग की गई है, उन्हें आरोपी के रूप में दोषी ठहराया जाना चाहिए।– याचिकाकर्ता की शपथ पर दी गई गवाही के साथ एफआईआर की सामग्री एक उचित संतुष्टि दर्ज करने के लिए पर्याप्त है कि पति के परिवार के सदस्यों ने शिकायत किए गए अपराधों में सक्रिय रूप से भाग लिया और**

उन्हें भी मुकदमा चलाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। – पुलिस के समक्ष याचिकाकर्ता के अहस्ताक्षरित पूरक बयान पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष सही नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर – शपथ पर दिया गया बयान जाहिर तौर पर पुलिस के सामने दिए गए बयान से ऊंचा होगा – ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा *319* के तहत आवेदन को खारिज करने का आदेश क्षेत्राधिकार की त्रुटि से ग्रस्त है और न्याय के गर्भपात को दर्शाता है और स्वाभाविक रूप से अवैध है। – याचिका मंजूर।

अभिनिर्णित , वह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वैधानिक रूप से सीआरपीसी की धारा **401** द्वारा प्रदत्त है। अवैधताओं की ऐसी विकृतियों के क्षेत्राधिकार की त्रुटियों के लिए विवादित आदेशों की जांच करने के लिए न्यायिक जांच को सीमित करता है, जिसके कारण न्याय का गर्भपात हुआ है। वह पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वैधानिक रूप से सीआरपीसी की धारा 401 द्वारा प्रदत्त है। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अवैधताओं की ऐसी विकृतियों के क्षेत्राधिकार की त्रुटियों के लिए आक्षेपित आदेशों की जांच करने के लिए न्यायिक जांच को सीमित किया गया है, जिसके कारण न्याय की हानि हुई है। यह ट्रायल कोर्ट को किसी आरोपी को पहले से ही दोषी करार दिए गए आरोपी के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 319 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई अपराधी अपने कुकर्मों के परिणामों से न छूटे। इन शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में कुछ हद तक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, न्यायालय संतुष्ट हो कि जिन व्यक्तियों को समन करने की मांग की गई है, उन्हें आरोपी के रूप में दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह "उचित संतुष्टि" रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री

पर आधारित होनी चाहिए, जो तर्क की प्रक्रिया से स्पष्ट होनी चाहिए जिससे आरोपी को बुलाने का आदेश दिया जा सके।

(पैरा 10)

इसके अलावा, माना गया कि क्रूरता और उत्पीड़न के संबंध में उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। पैसे, कूलर, फ्रिज, मोटर साइकिल और वॉशिंग मशीन की मांग के संबंध में विशेष आरोप हैं। बयान में विशेष रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बेटी को दहेज की मांग के कारण आरोपियों द्वारा मार डाला गया था। याचिकाकर्ता की जिरह पर गौर करने से पता चलता है कि पूरक बयान याचिकाकर्ता के सामने रखा गया था, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। एफआईआर की सामग्री, जब पीडब्लूएल के रूप में याचिकाकर्ता के बयान के साथ पढ़ी जाती है, तो इस न्यायालय को उचित संतुष्टि दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 ने शिकायत किए गए अपराधों के आयोग में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसलिए, उन्हें खड़े होने के लिए बुलाया जाना चाहिए। पहले से ही आरोपित अभियुक्तों के साथ मुकदमा। ट्रायल कोर्ट द्वारा लौटाया गया निष्कर्ष कि रिकॉर्ड पर सामग्री के बावजूद, उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को केवल संदेह के आधार पर नहीं बुलाया जा सकता है, यह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित नहीं है, बल्कि बयानों पर विकृत विचार पर आधारित है। आवेदन को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत खारिज करते हुए। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अहस्ताक्षरित पूरक बयान पर प्राथमिक निर्भरता रखी, जो पुलिस को दिया गया था, जिसमें उत्तरदाताओं नंबर 2 से 5 को किसी भी गलत काम से बरी कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के पुलिस को दिए गए पहले बयान पर ध्यान देते हुए, जिसमें उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को

शामिल किया गया है, साथ ही पीडब्लूएल के रूप में शपथ के उसके बयान पर, इन दो महत्वपूर्ण बयानों को खारिज करने के लिए कोई भी कारण नहीं बताया गया है।

(Para12)

इसके अलावा, यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, एक न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री के आधार पर एक उचित संतुष्टि यानी न्यायिक संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता होती है। शपथ पर दिया गया बयान जाहिर तौर पर पुलिस के सामने दिए गए बयान से ऊंचा होगा और इसलिए, इसे उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर तब जब याचिकाकर्ता ने शपथ पर अपने बयान के दौरान पूरक बयान से इनकार कर दिया हो।

(पैरा 13)

इसके अलावा, यह माना गया कि एक और आधार जिसके कारण ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया, वह यह था कि प्रतिवादी नंबर 2 से 5, जो पति के रिश्तेदार हैं, अलग रह रहे थे और इसलिए, वे अपराध नहीं कर सकते थे, जिसकी शिकायत की गई थी। अलग रह रहे पति के रिश्तेदारों के संबंध में कानून की ऐसी व्यापक और सामान्य व्याख्याओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पत्नी की मौत के आरोपी पति के रिश्तेदारों का केवल अलग रहना, रिश्तेदारों को दोषमुक्त करने की परिस्थिति नहीं हो सकती। प्रत्येक मामले को अपने

विशिष्ट तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियाँ अनुचित थीं।

(पैरा 14)

अशीत मलिक, याचिकाकर्ता के वकील।

जे.एस. तूर, ए.जी. हरियाणा अतिरिक्त. प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।

राहुल राठौड़, वकील वि.एस राठौर के लिए , प्रतिवादी 3 से 5 के वकील।

निर्णय

राजीव भल्ला, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने 8 जुलाई, 2005 के आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसके तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। प्रार्थना करते हुए कि निजी उत्तरदाताओं को मुकदमा चलाने के लिए बुलाया जाए।

(2) याचिकाकर्ता की बेटी गीता की शादी जतिंदर नाम के व्यक्ति से हुई थी। 8 अप्रैल, 2004 को, याचिकाकर्ता को टेलीफोन पर सूचना मिली कि उसकी बेटी और उसका पति मोटरसाइकिल चलाते समय नहर में गिर गए थे और हालांकि जतिंदर बच गए थे, लेकिन गीता का पता नहीं था। याचिकाकर्ता ने 9 अप्रैल 2004 को पुलिस के समक्ष एक बयान दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। आरोप था कि उनकी बेटी का पति जतिंदर, सास कमलेश, ससुर समम सिंह, सोनू पुत्र सरनाम सिंह, कोमल पत्नी सोनू दहेज से असंतुष्ट थे। अपनी शादी के तुरंत बाद, उनकी बेटी ने याचिकाकर्ता को बताया था कि उपरोक्त व्यक्तियों ने भैंस न लाने पर उसे परेशान किया था। कुछ दिनों के बाद, याचिकाकर्ता ने रुपये की व्यवस्था की। भैंस खरीदने के लिए 20,000 रुपये दिए और उसे अपनी बेटी के ससुर को सौंप दिया। एक महीने बाद, ससुराल वालों (प्रतिवादी संख्या 2 से 5) ने उसकी बेटी को पीटना और परेशान करना शुरू कर दिया ताकि उसे कूलर, फ्रिज और मोटर साइकिल लाने के लिए मजबूर किया जा सके। चूंकि वह इन मांगों को पूरा नहीं कर सका, याचिकाकर्ता अपनी बेटी को वापस ले आया। वह 3 मार्च, 2004 तक उसके साथ रही। इसके बाद, पंचायत के हस्तक्षेप पर, गीता को उसके वैवाहिक घर वापस भेज दिया गया। एक पखवाड़े के बाद, पिटाई और उत्पीड़न शुरू हो गया और मांग की गई एक टेलीविजन के लिए उठाया गया था। ये, संक्षेप में, याचिकाकर्ता के तथ्य हैं पुलिस को पहला बयान।

(3) इसके बाद, याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने पुलिस के समक्ष एक पूरक बयान दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि उसकी मृत बेटी ने दहेज के आरोपों के संबंध में उसे गुमराह किया था। उसने उसे बताया था कि उसका पति शुरू से ही उसे मारना चाहता था। उन्होंने

आगे कहा कि सरनाम सिंह, श्रीमती। कमलेश, श्रीमती कोमल और सोनू (प्रतिवादी संख्या 2 से 5) की गीता की मौत में कोई भूमिका नहीं थी। जांच के बाद चालान पेश किया गया और पति और उसके दो दोस्तों को आरोपी बनाया गया। उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को कॉलम संख्या 2 में रखा गया था।

(4) आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/120-बी/34 के तहत आरोप तय किए गए। याचिकाकर्ता 17 सितंबर, 2004 को गवाह के रूप में पेश हुआ और उसने बताया कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। उनके पति जतिंदर और उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 द्वारा उन्हें परेशान किया गया और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। संक्षेप में, उन्होंने 9 अप्रैल, 2004 को अपने पहले बयान में अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराया। जिरह के दौरान, उनका सामना किया गया अपने बाद के बयान के साथ, दिनांक 12 अप्रैल, 2004, यानी। पूरक बयान में उत्तरदाताओं क्रमांक 2 से 5 को दोषमुक्त किया गया और हत्या के लिए गीता के पति और उसके दोस्तों को दोषी ठहराया गया। उन्होंने इस बयान को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

(5) इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया। उसमें प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को पहले से ही दोषी ठहराए गए आरोपियों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाया जाए। 8 जुलाई, 2005 के आदेश के तहत ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया।

(6) याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर आवेदन को खारिज करना उचित नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में शपथ पर याचिकाकर्ता की गवाही को खारिज करने और पुलिस के समक्ष 12 अप्रैल, 2004 को दिए गए एक कथित अहस्ताक्षरित पूरक बयान पर भरोसा करके गंभीर गलती की। आगे यह तर्क दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट कथित पूरक बयान पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि जिरह के दौरान याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से इस तरह का बयान देने से इनकार किया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पुलिस के समक्ष दिए गए याचिकाकर्ता के मूल बयान को भी नजरअंदाज कर दिया। यह तर्क दिया गया है कि पुलिस के समक्ष दिए गए प्रारंभिक बयान और ट्रायल कोर्ट के समक्ष शपथ पर दिए गए बयान के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलेगा कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 ने वास्तव में अपराध किया था और इसलिए, उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। . आगे यह तर्क दिया गया है कि यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5, पति के रिश्तेदार हैं, उनके पक्ष में किसी अन्य परिस्थिति के अभाव में, गलत निहितार्थ का निष्कर्ष नहीं निकलेगा।

(7) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं क्रमांक 2 से 5 के वकील का तर्क है कि उत्तरदाता पति के रिश्तेदार हैं, जो अलग रहते हैं। उन पर पति के साथ करीबी रिश्ते के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के पूरक बयान ने उन्हें किसी भी गलत काम से बरी कर दिया और मृतिका के पति और उसके दोस्तों को फंसा दिया और इस प्रकार, चूंकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया, इसलिए मुकदमा अदालत में दायर किया गया।

यूटी ने सही ही आवेदन खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करते समय कोई अवैधता नहीं की, अर्थात् याचिकाकर्ता के पुलिस के समक्ष दिए गए बयान और अदालत के समक्ष उसकी गवाही और उसके बाद निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष यह है कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 ने कोई अपराध नहीं किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि ट्रायल कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र में कोई त्रुटि नहीं की है और लागू आदेश किसी अवैधता से ग्रस्त नहीं है, इसलिए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाए।

(8) हरियाणा राज्य के वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को दोषमुक्त करने के लिए पुलिस के समक्ष एक पूरक बयान दिया। की गई जांच में मृतिका के पति जतिंदर और उसके सह-आरोपी को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया। जैसा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को दोषमुक्त कर दिया है, आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अभ्यास में हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

(9) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकार्ड का अवलोकन किया है।

(10) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वैधानिक रूप से सीआरपीसी की धारा 401 द्वारा प्रदत्त है। अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों या ऐसी विकृतियों या अवैधताओं के लिए विवादित आदेशों की जांच करने के लिए न्यायिक जांच को सीमित करता है जिसके कारण न्याय का गर्भपात हुआ है।

सीआरपीसी की धारा 319 यह ट्रायल कोर्ट को किसी आरोपी को पहले से ही दोषी करार दिए गए आरोपी के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 319 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई अपराधी अपने दुष्कर्मों के परिणामों से बच न सके। इन शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में कुछ हद तक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, न्यायालय संतुष्ट हो कि जिन व्यक्तियों को समन करने की मांग की गई है, उन्हें आरोपी के रूप में दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह "उचित संतुष्टि" रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित होनी चाहिए, जो तर्क की प्रक्रिया से स्पष्ट होनी चाहिए, जिसके आरोपी को परिणामस्वरूप सम्मन जारी करने का आदेश दिया जाएगा।

(11) सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखी गई सामग्री। रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दर्ज की गई थी। और इसके समक्ष पीडब्लूएल के रूप में उपस्थित होते हुए याचिकाकर्ता की शपथ पर गवाही। याचिकाकर्ता ने पीडब्ल्यूएल के रूप में शपथ ली कि उत्तरदाताओं नंबर 2 से 5 ने दहेज की मांग उठाई, न ही उसकी बेटी को परेशान किया और पीटा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह बयान याचिकाकर्ता के पुलिस के समक्ष दिए गए पहले बयान के अनुरूप था। वर्तमान याचिका के साथ संलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न शपथ पर याचिकाकर्ता का बयान इस प्रकार है:-

"एमएस। चूंकि मृतक गीता मेरी बेटी थी। मैंने अपनी पुत्री गीता का विवाह आज दिनांक 9 मार्च 2003 को ग्राम कुरक के न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त जितेन्द्र के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न किया था। मैंने अपनी बेटी की शादी में अपनी क्षमता से अधिक दान दहेज दिया था, लेकिन आरोपी जितेंद्र, उसके पिता

सरनाम सिंह, उसकी मां कमलेश, उसका भाई सोनू और उसकी भाभी (सोनू की पत्नी) दहेज से खुश और संतुष्ट नहीं थे। सरनाम सिंह और कमलेश दोनों के साथ सोनू और कोमल आज अदालत में मौजूद हैं। मेरी बेटी गीता को शादी के 3-4 महीने बाद ही मायके भेज दिया गया। मेरी बेटी गीता ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि उसका पति, उसकी सास, ससुर उसका जेठ सोनू और जेठानी कोमल भैंस की मांग करने पर उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न कर रहे थे। गीता का फोन आने पर मैं उसके ससुराल गया जहां सरनाम सिंह, कोमल, कमलेश, सोनू और जितेंद्र ने फिर से मेरे सामने भैंस की मांग उठाई। मेरी बेटी गीता भी वहां मुझसे मिली और उसने मुझे बताया कि उपरोक्त लोग भैंस की मांग को लेकर उसे परेशान कर रहे थे और उसके साथ क्रूरता कर रहे थे। मैंने आरोपी व्यक्ति को समझाया. इसके बाद, मैं फिर से अपनी बेटी के वैवाहिक घर गया और रुपये का भुगतान किया। अन्य आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति में सरनाम सिंह को 20,000 रु. रुपये का भुगतान करने के एक महीने बाद। आरोपी व्यक्ति को 20,000 रुपये देकर मैं अपनी बेटी गीता को अपने घर ले आया। मेरी बेटी गीता ने अपनी मां और मुझे बताया कि उपरोक्त आरोपियों ने उसे कूलर, फ्रिज, मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन लाने के लिए फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। उसने हमें यह भी बताया था कि उपरोक्त सामान नहीं लाने पर आरोपी उसे मारते-पीटते थे। 3 मार्च, 2004 को जगराम 4-5 लोगों के साथ गीता को ग्राम कुरक स्थित वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए मेरे गांव पीपल शॉ आया। जगराम ने मुझे आश्वासन दिया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा गीता को उसके वैवाहिक घर में ठीक से रखा जाएगा और उपरोक्त घटना को दोहराया नहीं जाएगा। 4 मार्च 20041 को मैंने अपनी गीता को जगमाल आदि के पास भेज दिया। गीता का भाई अरुण भी अपनी बहन से मिलने उसके मायके जाता रहता था। गीता ने उसके भाई अरुण के सामने भी

अपना दुखड़ा सुनाया कि आरोपी व्यक्ति उसे मारता-पीटता था और दहेज का सामान लाने के लिए परेशान करता था। अरुण पंचायत के बाद यानी 4 मार्च, 2004 को गीता के घर गया था। 8 मार्च, 2004 को मुझे इस आशय का टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ कि जतिंदर और गीता करनाल से अपने गाँव वापस आते समय मोटर साइकिल सहित नहर में गिर गए थे और वह जतिंदर खुद को डूबने से बचाने में कामयाब रहा, जबकि मोटरसाइकिल और गीता का पता नहीं चल सका। उक्त घटना की जानकारी सरनाम सिंह ने मुझे दूरभाष पर दी थी. मैं अपने भाई राज पाल सिंह, भतीजे संजीव और अन्य लोगों के साथ कछवा घाट (पुल) पर आया जहां पुलिस ने मुझसे मुलाकात की। मैंने पुलिस को अपना बयान दिया जिसे लिखित रूप में बदल दिया गया। मेरा कथन Ex.PA है, इसमें बिंदु "ए" पर मेरे हस्ताक्षर हैं। कथन Ex.PA मुझे पढ़कर सुनाया गया था और मैंने इसकी शुद्धता के प्रतीक के रूप में बिंदु 'ए' पर हस्ताक्षर किए थे। दहेज की मांग को लेकर आरोपियों ने मेरी पुत्री गीता की हत्या कर दी।

Xxxx श्री बी.एस.राठौड़, आरोपी जीतेन्द्र के वकील।

मुझे रात करीब सवा नौ बजे एक टेलीफोनिक संदेश मिला था। 8 अप्रैल, 2004 को। मैंने पुलिस के सामने अपने बयान में कहा था कि सरनाम सिंह ने मुझे टेलीफोन पर घटना के बारे में सूचित किया था (एक्स.पीए के बयान के अनुसार जहां सरनाम सिंह का नाम नहीं है)। मैं रात करीब 11 बजे कछहवा पुल पर पहुंचा. 8 अप्रैल, 2004 को। पुल के पास पुलिस अधिकारी मौजूद थे और कुरक गांव का कोई व्यक्ति नहीं था। पास के गांव के 1-2 लोग जरूर वहां मौजूद थे.

पुलिस गीता व मोटर साइकिल की तलाश कर रही थी. मैंने शायद वहां मौजूद पुलिस को अपनी पहचान बता दी होगी. वहां पहुंचने के दो घंटे बाद कछाव पुल पर पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किया था. पॉजिस ने गाड़ी में बैठाकर मेरा बयान दर्ज किया था.' गोताखोर उस नहर में गीता और मोटर साइकिल की तलाश कर रहे थे. ड्राइवर पुलिस विभाग के नहीं थे। वे संख्या में 5-6 थे. मुझे नहीं पता कि सरनाम सिंह दिल के मरीज हैं या नहीं. यह सही है कि सरनाम सिंह की पत्नी कमलेश कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और उनका इलाज पी.जी.आई., चंडीगढ़ से चल रहा है। पुलिस ने मेरा दूसरा बयान भी दर्ज कर लिया था लेकिन मैं बयान दर्ज करने की तारीख नहीं बता सकता. मैंने 12 अप्रैल, 2004 को पुलिस के समक्ष कोई बयान नहीं दिया कि मैंने अपने पहले के बयान को अस्वीकार कर दिया है (एक्स.डीए के भाग ए से ए के साथ सामना किया गया है जहां यह दर्ज किया गया है)। कंवर पाल, पीडब्ल्यू मेरी भाभी (साली का लड़का) का बेटा है। वह पिछले दस साल से अधिक समय से करनाल में रह रहे हैं। अरुण कुमार पीडब्लू मेरा बेटा है. मेरे बेटे अरुण कुमार को आरोपी व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग के बारे में अच्छी तरह से पता था क्योंकि यह तथ्य खुद गीता ने उसे बताया था, कंवर पाल पीडब्ल्यू को दहेज के सामान यानी मोटर साइकिल फ्रिज की मांग के बारे में तथ्य की जानकारी नहीं थी, वह भैंस थी इत्यादि। मैं 8 अप्रैल 2004 को कुरक गांव नहीं गया और हम किछौ पुल के पास ही रहे। मैंने अपने बयान में यह नहीं बताया कि मुझे एक टेलीफोनिक संदेश मिला था कि गीता और जतिंदर की कुचा नहर के पुल के पास मोटर साइकिल पर जाते समय दुर्घटना हो गई थी (सांकेतिक बयान Ex.DA जिसमें यह दर्ज है)। मैंने पुलिस के समक्ष अपने बयान में यह नहीं कहा था कि कंवल पाल, पीडब्लू ने 10 अप्रैल, 2004 को बताया था कि जीतेन्द्र और अन्य लोग मिलकर मेरी बेटी की हत्या की साजिश रच रहे थे

(एक्स.डीए के सामने, जहां ऐसा दर्ज है)। मैंने पुलिस के सामने यह नहीं कहा कि मेरी बेटी गीता दहेज की मांग के संबंध में तथ्यों को गलत बता रही थी, वास्तव में यातना का कोई अन्य कारण था (बयान Ex.DA के साथ सामना किया गया जहां यह दर्ज किया गया है)। मैंने पुलिस के सामने यह नहीं कहा कि मेरी बेटी गीता इस तथ्य को गलत बता रही है कि उसे दहेज की मांग के कारण प्रताड़ित किया गया था (बयान Ex.DA के साथ जहां यह दर्ज किया गया है)। मैंने अपने बयान में पुलिस को यह नहीं बताया कि गीता की मौत में सरनाम सिंह, कमलेश, सोनू और कोमल की कोई भूमिका नहीं थी। (बयान Ex.DA के अनुरूप जहां यह दर्ज किया गया है)। यह सही है कि मैंने पुलिस के सामने कहा है कि यह हत्या का मामला है। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर मेरी बेटी की हत्या कर दी गयी. (सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन स्थानांतरित होने के कारण आगे की जिरह स्थगित कर दी गई है)।"

(12) ऊपर दिए गए बयान के अवलोकन से पता चलता है कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 के खिलाफ क्रूरता और उत्पीड़न के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। पैसे, कूलर, फ्रिज, मोटर साइकिल और वॉशिंग मशीन की मांग के संबंध में विशेष आरोप हैं। बयान में विशेष रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बेटी को दहेज की मांग के कारण आरोपियों द्वारा मार डाला गया था। याचिकाकर्ता की जिरह पर गौर करने से पता चलता है कि पूरक बयान, एक्स.डीए, याचिकाकर्ता को दिया गया था, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मेरी सुविचारित राय में, एफआईआर की सामग्री, जब पीडब्लूएल के रूप में याचिकाकर्ता के बयान के साथ पढ़ी जाती है, तो इस न्यायालय को उचित संतुष्टि दर्ज करने में सक्षम

बनाने के लिए पर्याप्त है कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 ने शिकायत किए गए अपराधों के आयोग में सक्रिय रूप से भाग लिया और, इसलिए , पहले से ही दोषी ठहराए गए आरोपियों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा लौटाया गया निष्कर्ष, कि रिकॉर्ड पर सामग्री के बावजूद, उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को केवल संदेह के आधार पर नहीं बुलाया जा सकता है, यह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित नहीं है, बल्कि बयानों पर विकृत विचार पर आधारित है। , यहाँ पहले उल्लेख किया गया है। आवेदन को खारिज करते समय, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अहस्ताक्षरित पूरक बयान पर प्राथमिक भरोसा किया, जो पुलिस को दिया गया था, जिसमें उत्तरदाताओं नंबर 2 से 5 को किसी भी गलत काम से बरी कर दिया गया था। पुलिस के सामने याचिकाकर्ता के पहले बयान पर ध्यान देते हुए, जिसमें उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 को शामिल किया गया है, साथ ही पीडब्लूएल के रूप में शपथ पर उसका बयान भी दिया गया है; इन दो महत्वपूर्ण बयानों को खारिज करने के लिए कोई भी कारण नहीं बताया गया है।

(13) जैसा कि यहां पहले देखा गया है, किसी आवेदन पर विचार करते समय, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत, एक न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री के आधार पर उचित संतुष्टि यानी न्यायिक संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता होती है। शपथ पर दिया गया बयान स्पष्ट रूप से पुलिस के सामने दिए गए बयान से अधिक महत्व रखता है और इसलिए, इसे उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर तब जब याचिकाकर्ता ने शपथ पर अपने बयान के दौरान पूरक बयान से इनकार कर दिया हो।

(14) एक अन्य आधार जिसके कारण ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया, वह यह था कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5, जो पति के रिश्तेदार हैं, अलग रह रहे थे और इसलिए, वे अपराध नहीं कर सकते थे, जिसकी शिकायत की गई थी। पति के अलग रहने वाले रिश्तेदारों के संबंध में कानून की ऐसी व्यापक और सामान्य व्याख्याएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं। पत्नी की मौत के आरोपी पति के रिश्तेदारों का केवल अलग रहना, रिश्तेदारों को दोषमुक्त करने की परिस्थिति नहीं हो सकती। प्रत्येक मामले को अपने विशिष्ट तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियाँ अनुचित थीं।

(15) ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, मैं संतुष्ट हूं कि विवादित आदेश क्षेत्राधिकार की त्रुटि से ग्रस्त है और न्याय के गर्भपात को उजागर करता है और इस प्रकार, स्वाभाविक रूप से अवैध है।

(16) ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, याचिका की अनुमति दी जाती है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा पारित 8 जुलाई, 2005 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, और उत्तरदाताओं संख्या 3 से 5 को मुकदमा चलाने के लिए बुलाने का निर्देश दिया जाता है। पहले से ही दोषी ठहराए गए आरोपी. ट्रायल कोर्ट, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर, उत्तरदाताओं संख्या 3 से 5 को बुलाएगा और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसे बुलाया नहीं जा सकता।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और

किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
नूँह, हरियाणा